Inadequate project preparation

Problems in acquisition of land.

Delays in environmental/forest clearance

Delays in finalisation of detailed engineering

Delays in supply of equipments.

Government constantly endeavours to improve the system of project implementation and have taken various measures which include—

Emphasis on preparation of realistic project implementation plan.

Setting up of Task Force|Empowered Committee for problem solving and speedy implementation of projects.

Issue of detailed guidelines to facilite environmental clearance .

Close follow up by concerned Ministries and project authorities with State Governments, equipment suppliers, contractors, consultants and other concerned agencies to minimise delays.

Issue of directions for ensuring continuity of tenure of project head until the completion of project and 2—3 years beyond to ensure accountability for project implementation.

राज्यों में जिलों का विभाजन

2140. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी मांझी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिले को सिद्धांत रूप में एक इकाई मानकर क्या केन्द्रीय सरकार अब इस दृष्टि से यह विचार करेगी कि राज्यों के तुलनात्मक रूप में बहुत बड़े क्षेत्र और आबादी वाले जिलों को छोटे जिलों में विभाजित कर दिया जाये ताकि वहां पर योजना और विकास से संबंधित कार्य को आसानी तथा सुचारू रूप से किया जा सके ;

(ख) क्या राज्य-सरकारों ने जिलों के पुनर्गठन के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) बड़े जिलों को छोटे जिलों में विभाजित करने के लिए बनाये गये मध्यप्रदेश के जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जिला आयोजन से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि "केवल प्रशासनिक आधार पर ही जिले का आकार भी अधिक प्रबंधकीय बनाया जाना चाहिए।" तथापि, जिलों के विभाजन का विषय राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है ।

(ख) जी, नहीं । योजना आयोग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) यह प्रश्न मध्यप्रदेश सरकार से संबंधित है ।

संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये मरीजों का डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में इलाज

2141. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये मरीजों को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के विभिन्न चिकित्सा विभागों में प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ डाक्टरों की अलग से भी कोई व्यवस्था है ; यदि हां, तो , प्रत्येक विभाग में उनके नाम तथा टेलीफोन नं० क्या-क्या हैं ; और